एक नजर

अल्मोड़ा पर्यावरण संस्थान की भूमि पर अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट ने दी राहत, डीएम को 12 माह में कार्रवाई के निर्देश

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा में हुए अतिक्रमण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पर्यावरण संस्थान को राहत देते हुए जिलाधिकारी को सभी अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी प्रत्यावेदन पर 12 माह में समिति बनाकर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पर्यावरण संस्थान की भूमि पर किए गए व्यापक अतिक्रमण मामले में सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन इनवारमेंट अल्मोड़ा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी भूमि पर व्यापक अतिक्रमण की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए जब प्रशासन को उनको हटाने के लिए बोला गया, तो प्रशासन की ओर से उचित मदद नहीं मिली। कोर्ट में अतिक्रमणकारियों ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उनको हटाने के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और वह अपनी ही भूमि पर हैं। सभी तथ्यों को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा से कहा कि वह एक समिति बनाकर उन सब लोगों को चिन्हित करें जो अतिक्रमणकारी हैं और इस बात को पुष्ट करें कि जैसा पर्यावरण संस्थान द्वारा कहा जा रहा है कि क्या वह पर्यावरण संस्थान की भूमि पर हैं। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट आ जाने पर 12 माह के भीतर कार्यवाही पूर्ण करें।

बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के बाहर मिला नवजात का भ्रूण, जांच शुरू

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। बीडी पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल के बाहर शुक्रवार सुबह सड़क किनारे सफाई के दौरान एक नवजात बच्चे का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सफाई कर्मियों ने भ्रूण पड़ा देखा तो इसकी सूचना तत्काल चिकित्सालय प्रबंधन को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने अपने स्तर पर जांच शुरू करने के साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी। बताया जा रहा है कि नवजात की उपचार के दौरान मौत हुई थी। हालांकि, भ्रूण चिकित्सालय परिसर के बाहर सड़क किनारे कैसे पहुंचा और इसके पीछे क्या कारण रहे, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। चिकित्सालय प्रबंधन इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है। जिला चिकित्सालय की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. द्रोपदी गर्ब्याल ने बताया कि बीते एक वर्ष के दौरान गर्भावस्था संबंधी जांच और उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंची नाबालिगों और महिलाओं के अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दूसरी ओर मल्लीताल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र रावत ने बताया कि पुलिस ने भ्रूण को पंचनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमॉर्टम के लिये डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी भेज दिया है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास कोई सीसी–टीवी कैमरे लगे नहीं मिले हैं। फिर भी पुलिस अपनी ओर से भ्रूण को यहां कौन और कैसे छोड़ गया, इसकी जांच कर रही है।

त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट पौड़ी पुलिस, बाजारों में पैदल गश्त तेज

स्वतंत्र चेतना

पौड़ी गढ़वाल। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पौड़ी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। जनपद के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पैदल गश्त के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी सर्वेश पंवार के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमें संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही हैं। साथ ही अराजक तत्वों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस टीमों ने बैंकों और ज्वेलरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, सुरक्षा उपकरणों और अन्य इंतजामों की जांच कर प्रतिष्ठान संचालकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने व्यापारियों और आमजन से बाजारों में सतर्कता बरतने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

राहुल गांधी की वोट बचाओ यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा : अमित शाह

उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का लक्ष्य, शाह बोले- 2027 में 65 पार

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ह्यवोट बचाओ यात्राह्ल को ह्यघुसपैठिया बचाओ यात्राह्ल करार दिया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी यात्रा निकालकर इसका विरोध कर रहे हैं। देश में घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, शुक्रवार की नमाज के लिए छुट्टी का प्रस्ताव लाने और राम मंदिर निर्माण का विरोध करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 65 पार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि पार्टी उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।



शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने उत्तराखंड राज्य के गठन को रोकने का काम किया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नौ नवंबर, 2000 को अलग राज्य बनाकर वर्षों पुराने सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे संवारने का काम किया है। उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है। बाबा केदारनाथ, बदरी विशाल, मां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल, हेमकुंड साहिब और हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ इस देवभूमि को विशिष्ट पहचान देते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोक्ष की कामना लेकर देवभूमि की ओर आता है और वह इस पवित्र भूमि को बार-बार प्रणाम करते हैं। गृह मंत्री ने राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा सहित विभिन्न स्थानों पर संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के साथ ही माधो सिंह भंडारी, तीलू रौतेली, गबर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी और जनरल बिपिन रावत सहित अनेक विभूतियों को याद कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। शाह ने राज्योत्सव को गौरव, सिद्धि और संकल्प का अवसर बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि और राज्य निर्माण का गौरव सभी को महसूस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विकास की दिशा में हासिल उपलब्धियां सिद्धि हैं। अब संकल्प है कि वर्ष 2045 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में उत्तराखंड देश का सबसे पहले विकसित होने वाला राज्य बने। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के साथ आम नागरिक की समृद्धि भी सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू यूसीसी के माध्यम से विवाह और तलाक से जुड़े मामलों में समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड के उदाहरण के बाद देश के 15 राज्य यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और भाजपा सभी राज्यों में इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिना सिफारिश और बिना किसी खर्च के 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया। गृह मंत्री ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण, सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, तीन लाख लखपति दीदियों के निर्माण, होमस्टे योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण व बलिदानी परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। किच्छा में एम्स के सेटेलाइट केंद्र और औद्योगिक स्मार्ट सिटी को भी उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाएं बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर पहाड़ के पानी और जवानी को पहाड़ के काम न आने देने वाली नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को लंबे समय तक मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था और पलायन के भरोसे छोड़ दिया था, जबकि भाजपा सरकार ने उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांव के रूप में देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें देश के पहले गांव के रूप में विकसित करने की सोच दी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 270 करोड़ रुपये की लागत से 51 सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे गांवों में युवाओं की वापसी का रास्ता खुल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और बुनियादी सुविधाओं के विकास को रोका जाता था। इसके विपरीत मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत किया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयास किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हरिद्वार स्टिंग प्रकरण, एससी-एसटी छात्रवृत्ति घोटाले, शराब नीति से जुड़े विवाद और कुमाऊं में खाद्यान्न से संबंधित कथित घोटालों का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने सरकारी धन का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हल्द्वानी में 29 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है और अब उत्तराखंड की बारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले 46 प्रतिशत मत और 57 सीटों तथा 2022 में मिले 44 प्रतिशत मत और 47 सीटों का उल्लेख किया। शाह ने कहा कि इस बार पार्टी को 65 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है।

मुख्यमंत्री धामी ने रखा उत्तराखंड के विकास का खाका

कहा-विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। कनेक्टिविटी, पर्यटन, उद्योग, स्वरोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान किए जाने को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने इसके लिए पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता



और अखंडता की मजबूत नींव रखी थी। अमित शाह उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम और तीन नए आपराधिक कानूनों जैसे निर्णय लिए गए हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से देश में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सहकार से समृद्धि अभियान से किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को भी नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान का सम्मान करते हुए अलग उत्तराखंड राज्य का सपना साकार किया था। वर्तमान सरकार राज्य आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, पर्यटन, उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय भ्रम और टकराव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और असहमति जताना सभी का अधिकार है, लेकिन युवाओं को भड़काना, अफवाह फैलाना और हिंसा को प्रोत्साहित करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति दोहरा रवैया अपनाने को भी अनुचित बताया। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर और रुद्रपुर में आयोजित ह्यलोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओह्ल अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों में जनता की व्यापक भागीदारी रही। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बजट की तुलना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का इस वर्ष का बजट करीब 54,928 करोड़ रुपये है, जबकि उत्तराखंड का बजट 1,11,703 करोड़ रुपये है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत बताया। धामी ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। मत्स्य विकास में हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। पर्यटन के क्षेत्र में बेस्ट एडवेंचर और बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन जैसे सम्मान तथा फिल्म निर्माण के अनुकूल वातावरण के लिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये, प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.74 लाख रुपये और आर्थिक वृद्धि दर 7.23 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उनके अनुसार, राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत से अधिक है। राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने अमित शाह को उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी, शॉल, गंगाजली और समुद्र मंथन का प्रतीक चिह्न भेंट किया। इन स्मृति चिह्नों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन भारतीय सभ्यता से जुड़े प्रतीकों को प्रस्तुत किया गया। राज्योत्सव कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत एवं डॉ. रमेश पोखरियाल ह्यनिशंकह्ल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट एवं बांसुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, मदन कौशिक, खजान दास, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, राम सिंह कैड़ा, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य एवं प्रदीप बत्रा, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल सहित विधायकगण, विभिन्न दायित्वधार ी, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रदेशवासी उपस्थित थे।

नैनीताल हाईकोर्ट में दीपावली अवकाश घोषित, अब 16 नवंबर को खुलेगा कोर्ट

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय में दीपावली का अवकाश घोषित कर दिया गया है, अब उच्च न्यायालय 16 नवंबर को खुलेगा। उच्च न्यायालय के कलेंडर के अनुसार दीपावली का अवकाश 7 से 13 नवंबर तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद अब कोर्ट 16 नवंबर को खुलेगा।

सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मैंने अपना पूर्व नाम वीना (VEENA) परिवर्तित कर वीना अरोड़ा (VEENA ARORA) रख लिया है। अतः अब से भविष्य में मुझे वीना अरोड़ा, पुत्री श्री दौलत राम सिडाना के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा।
पता: 25, जस्सा राम रोड, शिव मूर्ति लेन, होटल सिटी पैलेस, हरिद्वार।

अमित शाह के देहरादून आगमन पर कांग्रेस और उक्रांद का प्रदर्शन

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को देहरादून पहुंचने पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, जबकि उक्रांद कार्यकताओं ने मूल निवास, भू-कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

गणेश गोदियाल ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस मामले में न्याय और इससे जुड़े सवालों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी समाधान की मांग कर रही है। उन्होंने धनतेरस के दिन



अमित शाह की सभा आयोजित किए जाने पर भी सवाल उठाया। गोदियाल ने कहा कि भाजपा से जुड़े संगठनों ने एक नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी की रैली का त्योहार के दौरान आयोजन होने के आधार पर विरोध किया था। वहीं, उक्रांद कार्यकताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार से प्रदेश के मूलभूत मुद्दों पर जवाब मांगा। दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी प्रदेश बेरोजगारी, पलायन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अब तक मजबूत मूल निवास और भू-कानून लागू करने तथा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया गया। उक्रांद के केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने स्थानीय लोगों के लिए जमीन, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय, शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। दल के महानगर अध्यक्ष प्रबीन रमोला ने कहा कि प्रदेश में अनियोजित विकास, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण और पेयजल संकट जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। उक्रांद ने मूल निवास और सशक्त भू-कानून लागू करने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने तथा जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय जनता के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की।

धनतेरस पर पौड़ी के बाजारों में उमड़ी भीड़, देर शाम तक खरीदारी में जुटे रहे लोग

स्वतंत्र चेतना

पौड़ी गढ़वाल। धनतेरस पर्व को लेकर पौड़ी शहर के बाजारों में रौनक छाई रही। शुक्रवार को सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिन चढ़ने के साथ ही बाजारों में भीड़ बढ़ती गई। धारा रोड सहित शहर के अन्य प्रमुख बाजारों में दिनभर चहल-पहल बनी रही।

होटलों औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया अग्निशमन निरीक्षण

स्वतंत्र चेतना

नई टिहरी। दीपावली को सुरक्षित मनाए जाने के उद्देश्य से टिहरी पुलिस ने एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर जिलेभर में होटलों, रेस्टोरेंटों सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण एवं प्रशिक्षण अभियान चलाया। अग्निशमन विभाग ने अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी दी। शुक्रवार को अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में नरेंद्रनगर क्षेत्र के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं औद्योगिक इकाइयों का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों एवं आपातकालीन निकास मार्गों का जायजा लिया गया। साथ ही प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही एवं बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

नरेंद्र सिंह नेगी और हेमंत पांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार

अमित शाह और मुख्यमंत्री धामी ने किया सम्मानित, दो-दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और अभिनेता हेमंत पांडे को राज्योत्सव समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के तहत वर्ष 2024 के लिए नरेंद्र सिंह नेगी और वर्ष 2025 के लिए हेमंत पांडे का चयन किया गया था। दोनों कलाकारों को दो-दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने लोकगीतों के माध्यम से उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, परंपराओं,



सामाजिक सरोकारों और जनभावनाओं को स्वर दिया है। उनके योगदान ने प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं, अभिनेता हेमंत पांडे ने अपने अभिनय से भारतीय फिल्म और मनोरंजन जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने विभिन्न फिल्मों और धारावाहिकों के माध्यम से उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, क्षेत्रीय सिनेमा और कला जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र। सीआईएन नंबर: U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (ऑथराइज्ड ऑफिसर) के रूप में, और धारा 13(12) के साथ ह्यसिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 से मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैंने नीचे बताए गए कर्जदारों को एक 'डिमांड नोटिस' जारी किया था। इसमें उनसे कहा गया था कि वे नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर उसमें बताई गई रकम चुका दें। कर्जदारों द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, मैंने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और संबंधित नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदारों, गारंटरों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें। यदि ऐसा कोई लेन-देन किया जाता है, तो वह वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार (चार्ज) के अधीन होगा, जिसमें नीचे बताई गई रकम, उस पर लगने वाला ब्याज और अन्य खर्च आदि शामिल होंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या और नाम उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं एलएएन न.	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति/संपत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि और प्रकार
1.	रमेश गुप्ता (उधारकर्ता), बाला गुप्ता (सह-उधारकर्ता) LP0000000021460	18/अगस्त/26 17/अगस्त/26 को 2234097/- रुपये	अचल संपत्ति: वह पूरी जमीन जिसका नगर निगम नंबर 58/3 (पुराना नंबर 522) है, जो ब्लॉक-3, इंदिरा कॉलोनी, नई बस्ती, चुखूवाला, देहरादून में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 128.06 वर्ग मीटर (26.5 फीट X 52 फीट = 1378 वर्ग फीट) है और यह उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय, देहरादून में विधिवत पंजीकृत है। पता: ब्लॉक-3, इंदिरा कॉलोनी, नई बस्ती, चुखूवाला, देहरादून - 248001, उत्तराखंड। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर ह्न दूसरों की संपत्ति, दक्षिण — राजकुमार की संपत्ति, पूर्व ह्न प्रकाश की संपत्ति, पश्चिम ह्न 10 फीट चौड़ा रास्ता।	प्रतीकात्मक कब्जा 04/11/2026 को लिया गया

दिनांक: 07.11.2026
स्थान: देहरादून
अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
GRIHUM HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan
रजिस्टर्ड ऑफिस: 6 वीं फ्लोर, बी बिल्डिंग, गंगा टुएनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र-411014 ब्रांच ऑफ यूनिट: आर.के. टॉवर, 2nd फ्लोर, स्वामी हरिचुरम ट्रस्ट के सामने, कनखल रोड, आर्या नगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार, यू.के. - 249407

ई-ऑक्शन बिक्री सूचना
सरफेसी एक्ट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना: वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("एक्ट") की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत। सर्वसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे इसके बाद अधिनियम के अनुसार "सुरक्षित लेनदार" कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई हैं, जिनका भौतिक कब्जा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री "जैसी जहाँ है", "जैसी स्थिति में है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 23-11-2026 को ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं जो वेबसाइट: https